Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

1857 का विद्रोह

Sushma Devi*

PGT History, NCC Senior Model School, Ambala City, Haryana

सारांश – *1757 में प्लासी की लड़ाई और 1857 के विद्रोह के बीच ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने सौ वर्ष पूरे कर लिये थे। ब्रिटिश शासन ने अपने इन 100 वर्षों में "सूक्ष्मता के साथ हिंसा का एकाधिकार" स्थापित किया था, इसलिए उसकी प्रजा ने भी उसका जवाब उतनी ही अधिक जवाबी हिंसा के साथ दिया। अगर विद्रोहियों को सार्वजनिक रूप से फांसी देना, तोप से उड़ाना और मनमाने ढंग से गाँवों को जलाना अंग्रेजों के विद्रोह-विरोधी कदमों में शामिल था, तो विद्रोहियों ने भी निर्ममता से स्त्रियों और बच्चों समेत गोरे नागरिकों की हत्या की। इस अर्थ में कानपुर का 27 जून 1857 का हत्याकांड 'अतिचार' का कृत्य था, क्योंकि यह उपनिवेशितों की देशी हिंसा का कृत्य था, जिसने उपनिवेशकों की हिंसा के एकाधिकार को तोड़ा।[1] यूं तो 1857 के विद्रोह के फूटने से पूर्व भी भारत में कई स्थानों पर विद्रोह के स्वर फूटने लगे थे जैसे - (1) 1764 में बक्सर के युद्ध के समय हैक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीरकासिम से मिल गये। (2) 1806 ई. में बेल्लोरमठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक, धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्ताक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झण्डा फहराया। (3) 1842 ई. में ब्रमा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही उचित भत्ता न मिलने के कारण विद्रोह कर दिया। (4) 1825 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हुआ। (5) 1844 में 34वीं एन.आई. तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इंकार कर दिया। (6) 1849-50 में पंजाब स्थित गोविन्दगढ़ की एक रैजिमेंट विद्रोह पर उतर आई इन्हीं घटनाओं ने 1857 के उस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आरंभिक संकेत जनवरी के अंत में देखे गए। उस समय कलकत्ता के पास दमदम में सिपाहियों में यह अफवाह फैलने लगी कि नई एनफील्ड राइफल के कारतूतों में, गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। चूँकि भरने से पहले इन कारतूसों को दाँतों से काटना पड़ता था, इसलिए अपने धर्म और जाति के नाश और ईसाई बनाए जाने के षड्यंत्र के बारे में सिपाहियों का पुराना शक पक्का हो गया। कलकत्ता के पास बैरकपुर में मंगल पांडे नाम के एक सिपाही ने 29 मार्च को एक यूरोपीय अफसर पर गोली चला दी और यूरोपीय अफसरों ने जब उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया तो उसके साथियों ने मानने से मना कर दिया। शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट मार्शल किया गया और अप्रैल के आरम्भ में फांसी दे दी गई, जिससे सिपाहियों में और ज्यादा असंतोष फैल गया। आने वाले दिनों में अवज्ञा, भड़कावे और लूटपाट की खबरें, अंबाला, लखनऊ और मेरठ छावनियों से आई और आखिर 10 मई को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने उन गिरफ्तार साथियों को छुड़ा लिया, जिन्होंने नए कारतूस को स्वीकार करने से मना कर दिया था, उन्होंने अपने यूरोपीय अफसरों को मार डाला और दिल्ली की ओर बढ़ चले, उन्होंने 11 मई को बुढे मुगल बादशाह बहादुरशाह जफर को हिन्दुस्तान का बादशाह घोषित किया।[2] दिल्ली के बाद यह विद्रोह जल्द ही पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध के दूसरे सेना-केन्द्रों तक फैल गया और जल्द ही इसने एक नागरिक विद्रोह का रूप ले लिया। हताशा से भरे गर्वनर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 19 जून को लिखा, "रूहेलखण्ड और दोआबे में दिल्ली से कानपुर और इलाहाबाद तक देश न केवल हमारे विरुद्ध बगावत कर बैठा है, बल्कि एक सिरे से विधिविरुद्ध हो चुका है।[3] भले ही 1857 का विद्रोह असफल रहा तो परन्तु इसने भारतीयों के लिए आजादी के द्वार खोलने का काम किया। इस विद्रोह के बाद कम्पनी ने भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेकर बोर्ड ऑफ़ कन्ट्रोल और बोर्ड ऑफ़ डाइरैक्टर्स को समाप्त कर दिया।*

मुख्य शब्द: *विद्रोह, स्वरूप, प्रसार, असफलता, परिणाम।*

----------X----------

विद्रोह के कारण:

1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद हैं। अंग्रेजी और भारतीय विद्वानों में अधिकाश विद्रोह का कारण सैनिकों की शिकायतों और चरबीयुक्त कारतूस को मानते हैं। परन्तु आधुनिक खोजों से यह बात करीब-करीब सिद्ध हो जाती है कि सैनिक असंतोष के लिए चरबीयुक्त कारतूस तो एकमात्र कारण है न कि

www.ignited.in

सर्वाधिक कारण। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की 'व्यपगत नीति' और वैलेजली की 'सहायक संधि' ने विद्रोह को जन्म देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। डलहौजी ने अपनी व्यपगत नीति द्वारा जैतपुर, सम्भलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया और अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया तथा भूतपूर्व पेशवा की पेंशन जब्त कर ली तथा बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुबमीनार में रहने का आदेश दिया। राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊँचे पद तक नहीं पहुंच पाता था, न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना जाता था। कंपनी की भू-राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बम्बई में स्थापित ईनाम कमीशन ने अपनी सिफारिशों के आधार पर करीब 20000 जागीरों को जब्त कर लिया। स्थायी बंदोबस्त, रैय्यतवाड़ी व्यवस्था और फिर महालवारी व्यवस्था द्वारा किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ। धार्मिक कारणों में कंपनी द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वाले लोगों को पैतृक सम्पत्ति का हकदार माना गया, नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा दी गई। सी.ए. बेइली के अनुसार, एरिक स्टोक्स ने जो बात साबित की है, यह है कि 1857 का भारतीय विद्रोह कोई एक आंदोलन न था अनेकों (आंदोलन) थे।[4] अतः कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह अनेकों राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से शुरू हुआ और एनफील्ड रायफल के कारतूसों ने इसमें आग में घी जैसा काम किया।

रणजीत गुहा लिखते हैं, "उन्होंने हथियार उस क्षेत्र को वापिस पाने के लिए उठाए जिसे वे अपने पूर्वजों का संसार मानते थे।"[5] विद्रोह के दौरान उल्लेखनीय धार्मिक एकता देखने को मिली क्योंकि सब इस बात पर सहमत थे कि हिन्दुस्तान एक समान हिन्दुओं और मुसलमानों का था।[6]

विद्रोह का प्रसार:

भारतीय स्वतंत्रता हेतू प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 एन.आई. तथा एल.सी. की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इंकार कर विद्रोह कर दिया तथा एक उच्चाधिकारी की हत्या कर दिल्ली की और रवाना हो गए। देखते-देखते विद्रोह ने अपनी चपेट में कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, झांसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, ग्वालियर को ले लिया।

विद्रोह की असफलता के कारण:

विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख था एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी न कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था, एक तरफ अवध, रूहेल खण्ड तथा उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह का नेतृत्व किया वहीं पटियाला, जींद, ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की। जहां विद्रोहियों के पास इक्का-दुक्का (तांत्याटोपे, लक्ष्मीबाई) नेता थे, वहीं कंपनी के पास लारेन्सबंधु, निकोलस आउट्रम, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य सेनापति थे, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही एक ऐसी भावना थी जिसके कारण विद्रोह एकजुट थे, अन्यथा उनके पास न तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी, न ही भविष्य की योजना। विद्रोह के बारे में जॉन लारेन्स ने कहा कि "यदि उनमें (विद्रोहियों में) एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते।

विद्रोह का स्वरूप:

1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। यह विवाद मुख्यतः तीन बिन्दुओं पर आधारित है सैनिक विद्रोह, एक राष्ट्रीय संघर्ष या भारतीय स्वतन्त्रता का प्रथम संघर्ष। अधिकतर अंग्रेज इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह भर मानते हैं जिनमें अग्रणी हैं सर जॉन सीले। सीले के अनुसार, "यह विद्रोह पूरी तरह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण सैनिक विद्रोह था। पर इनका कथन सही साबित नहीं होता, क्योंकि इस विद्रोह में सैनिकों के साथ-साथ किसानों तथा आम लोगों की भी भागीदारी थी। इस बात को स्वीकार करना होगा कि, 'अंग्रेजों के विरुद्ध' युद्ध किसी राट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं था, क्योंकि 1857 में भारत राजनीतिक दृष्टि से एक राष्ट्र था ही नहीं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह निःसंदेह साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रवादी था क्योंकि इसमें हिन्दुओं और मुसलमानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और दोनों का एक ही लक्ष्य था, साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फैंकना, लेकिन विद्रोहियों में राष्ट्रीयता की संकल्पना का पूर्ण अभाव था।

विद्रोह का परिणाम:

1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद 'ब्रिटिश क्राउन' ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार

www.ignited.in

वापस ले लिए। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल और बार्ड ऑफ़ डाइरैक्टर्स को समाप्त कर दिया। 1 नवम्बर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लार्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध करवाना लोगों के प्राचीन अधिकारों और रिवाजों के प्रति सम्मान व्यक्त करना आदि वायदे क्राउन द्वारा भारतीय जनता से किये गए। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके इसके लिए 'भारत सरकार अधिनियम' 1858 पारित हुआ जिसके द्वारा पिट्स इंडियन एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था समाप्त हो गई। 1857 के विद्रोह के बाद सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियनों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सैनिक की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से 'फूट डालो राज करो' की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। वायसराय कैनिंग के समय में 1861 का इण्डियन काउंसिल एक्ट, 1861 इण्डियन हाइकोर्ट एक्ट, 1861 का इण्डियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया।

संदर्भ

1. मुखर्जी 1998: 23 और आगे।

2. टेलर 1997: 31-49.

3. मेटकॉफ़ 1965: 68.

4. बेइली 1986: 226.

5. गुहा 1994: 318.

6. रे 1993: 133-82.

Corresponding Author

Sushma Devi*

PGT History, NCC Senior Model School, Ambala City, Haryana